

13.00 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bapusaheb Parulekar. He will be followed by Shri Ramavatar Shastri.

(vii) NEED TO GIVE DIRECTION TO MOGHUL LINES FOR REPLACEMENT OF OLD SHIPS OPERATING ON WEST COAST OF KONKAN MAHARASHTRA.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): Under Rule 377 I would like to mention the following matter of urgent public importance.

Since nationalisation of steamer service since 1973 on the West Coast of Konkan in Maharashtra, Moghul Lines are operating two ships on this line. Prior to the nationalisation Chowgule Steamship Company was operating three ships on this line and prior to that, over a period of 75 years Bombay Steam Navigation Company was operating more than four ships on this line. This steamer service was popularly known as Konkan Service as the ships operating on this line used to call at many ports on the coast of Konkan between Bombay and Panjim. Ships of Bombay Steam Navigation Company used to call at 20 ports and Chowgule Company used to call at ports and the Moghul Lines used to call at 11 ports regularly three ports once a week. This Steamer Service was nationalised as Chowgule Steamships requested a fare hike. But since the nationalisation there is 100 per cent increase in the fare and since 1977 Moghul Lines are calling now at four ports between Bombay and Panjim. The two ships operated by Moghul Lines on this line are old and have outlived their lives. Ships of Moghul Lines have ceased to call the port of Ratnagiri which is the district place and where lakhs of rupees have been spent for construction of an all-weather port. There is no air service nor a railway line in the district of Ratnagiri and the road transport is totally insufficient to cope with the traffic.

I, therefore, request that the Government should direct the Moghul Lines

to replace the two old ships by introducing new ships with low draught and further direct the company to call at all the ports which ships of Chowgule Steamships used to call at so as to meet the urgent need of the people. I also request the Government to reduce the fare and consider the feasibility of the operation of Hydrofile and Hovercraft service on this line.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramavatar Shastri.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Who will follow?...No follower?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He will be followed by the next item.

(viii) ADEQUATE SUPPLY OF FOODGRAINS TO BIHAR FOR PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सरकार का दावा है कि संपूर्ण देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सफलता पूर्वक संचालित की जा रही है। सरकार की ओर से उसे और मजबूत करने की बात भी कही जाती है। परन्तु वास्तविकता कुछ और है।

सरकार का यह भी दावा है कि उसके पास अन्न भण्डार भरपूर है जिसके आधार पर राशन की दुकानों में अनाज की कमी नहीं होने दी जायेगी। लेकिन आये दिन समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबरों से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार राज्यों के लिए निर्धारित कोटा भी उन्हें नहीं दे पाती जिसका प्रभाव राशन की आपूर्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है।

पटना बिहार की राजधानी है। वहां राशन की दुकानों की संख्या 570 है। परन्तु किसी भी दुकान को समय पर और पूरा गल्ला नहीं दिया जाता। इधर तो प्रति यूनिट राशन की सप्लाई में भारी कमी कर दी गई है। सन् 1977 से पहले सरकार एक माह में प्रति यूनिट

छः किलो गेहूँ और यदाकदा कुछ चावल की सप्लाई करती थी। बाद की सरकार ने उसमें कमी कर उसे प्रति यूनिट साढ़े पांच किलो माह्वारी निर्धारित किया था। सन् 1980 के चुनाव के बाद पुनः जब नई सरकार बनी तो प्रति यूनिट गेहूँ का कोटा पुनः छः किलो निर्धारित किया गया। परन्तु आश्चर्य और दुःख की बात है कि इन दिनों राशन कार्डधारियों को प्रति यूनिट एक किलो के हिसाब से गेहूँ और इससे कुछ अधिक चावल की सप्लाई की जा रही है जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं में भारी असंतोष है। इसका प्रभाव मंहगाई वृद्धि पर पड़ रहा है। अगर पहले की तरह उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट छः किलो गेहूँ नहीं दिया गया तो कितने गरीबों के भूख से मर जाने का खतरा पैदा हो गया है।

13.03 hrs.

[SHRI CHANDRAJIT YADAV in the Chair]

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह बिहार को यथेष्ट मात्रा में गल्ले की सप्लाई करने की व्यवस्था करे ताकि पटना नगर और दूसरे जिलों के उपभोक्ताओं को पहले की तरह प्रति व्यक्ति माह में 12 किलो गेहूँ मिल सके।

13.03 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1981-82—
Contd.

MINISTRY OF AGRICULTURE—Contd.
and

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION—
Contd.

MR. CHAIRMAN: Shri Mohanbhai Patel. Will you please continue? You were on your legs. You have

already taken thirteen minutes. You will have to conclude now.

श्री मोहन भाई पटेल (जूनागढ़) : माननीय सभापति जी, मैंने रेस्यूनेटिव प्राइज़ किसानों को देने के बारे में अपने वक्तव्य में बताया था, उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि आज एग््री-कल्चर प्राइज़ कमीशन में जनता का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, उसमें सब आफिसर्स जुड़े हुए हैं। मेरा सुझाव है कि भारत के सभी जोन्स से कृषि से सम्बन्धित लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व देना चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए।

आज देश में पेस्टीसाइड्स की जरूरत बढ़ती जा रही है, इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है और इसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। इसके उत्पादन में इतनी मुनाफाखोरी है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कई चीजें ऐसी हैं कि अगर इपोर्ट की जाएं तब भी महंगी है। कई ऐसी हैं उनका उत्पादन किया जाए तो और भी अधिक महंगी होती है। एक मिसाल मैं देना चाहता हूँ— एक दवा है पैराथियान, यह बाहर से मंगाई जाती है तो 32 रुपये किलो मिलती है और अगर इसका उत्पादन करते हैं तो जो कम्पनी उत्पादन करती है इसको 44 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचती है। इस तरह से 12 रुपये किलो अधिक लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सब कम्पनियों को नेशनलाइज़ किया जाना चाहिए, जिससे उचित दामों पर पेस्टी साइड्स मिल सकें।

सभापति जी, भारत में एक करोड़ टन आइल सीड की पैदावार होती है, उसमें अन्न करने से 60 लाख टन आइल